बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 27 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 04 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

जम्हूरियत हिंदुस्तान की शान है - अल्लमा जाबिर हुसैन सिद्दीकी

हजारीबाग । सोमवार को नुतन नगर, हजारीबाग मोहम्मद शरीफ़ के आवास पर प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लमा जाबिर हुसैन सिद्दीकी ने एक महान सभा को संबोधित करते हुए फरमाया के हमारे हिंदुस्तान की शान डेमोक्रेटिक है,लोकतांत्रिक है, जम्हूरियत है जो हमारे मुल्क की शान है। हमारे इस मुल्क की आजादी में हिंदुस्तान के हर धर्म के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। सबकी यह आजादी है कि वह अपने-अपने धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर कोई हमारी जम्हूरियत को नुकसान पहुंचता है तो उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की शान ही है कि हम आजादी के साथ अपने अपने मजहब अपने-अपने धर्म के वसूलों पर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं

अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौता दर्दनाक अनुभव बना, कांग्रेस ने ट्रंप का नाम लेकर केंद्र को घेरा

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दरअसल, ट्रंप ने एक बार फिर एक इंटरव्यू में दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को व्यापार के जरिए रोका था। पार्टी ने कहा कि अमेरिका के साथ होने वाला संभावित व्यापार समझौता अब भारत के लिए एक दर्दनाक अनुभव बन गया है कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा, एक समय कहा गया था कि भारत नवंबर 2025 में क्वाड (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का समूह) के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, लेकिन अब वह नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, एक समय यह भी कहा गया था कि अमेरिका के साथ सबसे पहले व्यापार समझौता करने वालों में भारत होगा। वह तथाकथित समझौता अब एक कठिनाई बन गया है, जबकि अमेरिका को निर्यात घट रहे हैं और यहां रोजगार

खो रहे हैं। मेश ने कहा कि इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने 57वीं बार यह दोहराया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अचानक और अप्रत्याशित रूप से कैसे रोका और इसकी पहली घोषणा वॉशिंगटन से हुई, न कि नई दिल्ली से। कांग्रेस नेता ने ट्रंप का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने व्यापार और शुल्क का उपयोग करके भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रोका।ट्रंप ने अमेरिकी टीवी नेटवर्क को दिए साक्षात्कार में कहा, अगर व्यापार और शुल्क नहीं होते, तो मैं यह समझौते नहीं करा पाता। उदाहरण के लिए, भारत हमारे साथ बहुत व्यापार करता है। वे पाकिस्तान के साथ परमाणु युद्ध करने वाले थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं होते, तो आज लाखों लोग मारे जाते। उन्होंने कहा, वह बहुत बुरा युद्ध होने वाला था। मैंने दोनों देशों से कहा कि अगर उन्होंने जल्दी कोई समझौता नहीं किया, तो वे अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने समझौता किया, युद्ध रुक गया। वह परमाणु युद्ध होता।÷ कांग्रेस ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि स्वयंभू 56 इंच का सीना अब पूरी तरह सिमट चुका है और उजागर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग हर दूसरे द्विपक्षीय या वैश्विक सम्मेलन में भारत-पाकिस्तान के साथ-साथ कई और देशों के विवादों को खत्म कराने का दावा करते आ रहे हैं। सितंबर में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए दावा किया था कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोका था। भारत ने हमेशा यह रुख रखा है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की समझ दोनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (डीजीएमओ) के बीच सीधे संवाद से बनी थी।

दिल्ली में इंडिया गेट हुआ गायब, आप-कांग्रेस ने कहा, धुंध पर बीजेपी का असली रंग उजागर; शिवसेना ने भी उठाए सवाल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति को लेकर बीजेपी की आलोचना शुरू कर दी हैराजधानी में पिछले कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब और बहुत खराब श्रेणी के बीच दर्ज किया जा रहा है। राजधानी में धुंधले दिखाई दे रहे इंडिया गेट की एक तस्वीर साझा करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह प्रतिष्ठित संरचना गायब हो गई है। आप ने एक पोस्ट में कहा, दिल्ली में इंडिया गेट गायब हो गया है। सरकार वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ चाहे जितना भी छेड़छाड़ कर ले, इंडिया गेट धुंध के पीछे गायब होकर भाजपा का असली रंग उजागर कर चुका है।आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोगों के मोबाइल फोन पर अधिकांश एप्लीकेशन सरकार के वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों से डेटा ले रहे हैं। भारद्वाज ने कहा, आप अपने मोबाइल फोन पर जो एक्यूआई देखते हैं, अधिकांश ऐप्स दिल्ली और केंद्र सरकार के एक्यूआई निगरानी स्टेशनों से डेटा लेते हैं। यदि आप आईफोन का मौसम ऐप देखें, तो वे केवल सरकारी निगरानी स्टेशनों DPCC, CPCB और IND से डेटा लेते हैं। केवल कुछ ऐप्स के पास अपने स्वयं के निगरानी स्टेशन हैं, जैसे कि अमेरिकी दूतावास। आप और कांग्रेस के अलावा, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी दिल्ली के प्रदूषण को चिंताजनक बताया। ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल उठाया, यादा चिंताजनक तो असली एक्यूआई के आंकड़े छिपाने की रणनीतियां हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को इस स्थिति को स्वीकार करने और जलवायु कार्रवाई पर सामाजिक-राजनीतिक सहमति बनाने में क्या दिक्कत है? सौरभ भारद्वाज एक वीडियो में दिल्ली में एक वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी केंद्र के बाहर दिखाई दे रहे थे। वीडियो में, दिल्ली के पूर्व मंत्री ने बताया कि ट्रक दिल्ली नगर निगम के थे। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि ट्रक प्रदूषण निगरानी स्टेशन के आसपास दिन-रात पानी छिड़क रहे थे।

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, 7 नवंबर को आएगा फैसला

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई की। इस दौरान पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को छोड़कर बाकी सभी रायों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव मौजूद रहे। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि वह 7 नवंबर को मामले में फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजनिया की तीन जजों वाली विशेष बेंच ने दर्ज किया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अदालत में मौजूद हैं। हालांकि, केरल के मुख्य सचिव की जगह प्रधान सचिव पहुंचे थे, जिसे लेकर आवेदन को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस दौरान बेंच ने आंध्र प्रदेश की ओर से पेश वकील से पूछा कि पिछली सुनवाई की तारीख पर अनुपालन हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया

गया। कोर्ट ने इस मामले में पशु कल्याण विभाग (एनिमल वेलफेयर बोर्ड) को भी वादी बनाए जाने को कहा। इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अधिकांश रायों ने अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल कर दिए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 7 नवंबर को फैसला सुनाने की बात कही और आदेश दिया कि इस तारीख को मुख्य सचिवों की सशरीर पेशी जरूरी नहीं होगी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर उसके आदेश के अनुपालन में कोई कमी की जाती है तो वह फिर से मुख्य सचिवों को पेशी के लिए बुला सकता है। इससे पहले 27 अक्तूबर को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने रायों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया था कि वे तीन नवंबर को अदालत में सशरीर पेश होकर यह स्पष्ट करें कि 22 अगस्त के आदेश के बावजूद अनुपालन हलफनामे क्यों दाखिल नहीं किए गए। उस समय अदालत ने आदेशों का पालन न होने पर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि 27 अक्तूबर तक पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को छोड़कर किसी राय या केंद्र शासित प्रदेश ने अनुपालन हलफनामे दाखिल नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को रायों और केंद्रशासित प्रदेशों से पूछा था कि पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुपालन के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं।

वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण समयसीमा बढ़ाने की मांग, एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यह याचिका दायर की है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट पीठ ने मामले को बीती 28 अक्तूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था, लेकिन उस वक्त सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। ओवैसी की तरफ से वरिष्ठ वकील निजाम पाशा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। पाशा ने सीजेआई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ से इस मामले पर तुरंत सुनवाई की अपील की। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, सशक्तिकरण और विकास के लिए MEED पोर्टल की शुरुआत की थी, जिस पर देशभर में मौजूद सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल विवरण

दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह पोर्टल 6 जून को लॉन्च किया गया था और छह माह के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों को इस पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। वकील निजाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील कर वक्फ संपत्ति के पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने की मांग की। पाशा ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह माह का समय दिया गया था, लेकिन पांच महीने का समय तो सुनवाई के दौरान बीत गया और अब सिर्फ एक माह का समय बचा है। इससे पहले 15 सितंबर को एक अंतरिम आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ मुख्य प्रावधानों पर रोक लगा दी, जिसमें एक क्लॉज यह भी था कि पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ बना सकता है। हालांकि अदालत ने पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कानून से वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि नए संशोधित कानून में यूजर द्वारा वक्फ प्रावधान को हटाने का केंद्र सरकार का आदेश पहली नजर में मनमाना नहीं था। यूजर द्वारा वक्फ का मतलब एक ऐसी प्रथा से है जहां किसी संपत्ति लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल के आधार पर धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती (वक्फ) के रूप में मान्यता दी जाती है, भले ही मालिक द्वारा वक्फ की कोई औपचारिक, लिखित घोषणा न की गई हो।

सुप्रीम कोर्ट ने माकपा की याचिका दूसरे पीठ के पास भेजी, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई-एम) की उस याचिका को दूसरी पीठ के पास भेज दिया, जिसमें उसने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दलों के स्थायी झंडे के डंडे (फ्लैग पोल) हटाने का निर्देश दिया गया था। यह मामला जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ के सामने आया था। मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि इसी तरह की एक याचिका पहले जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनी गई थी। इसलिए यह मामला उसी पीठ को भेजा जाए। अदालत ने कहा, इस मामले को जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाए और यदि आवश्यकता हो तो मुख्य न्यायाधीश से उचित आदेश लिए जाएं। मद्रास हाईकोर्ट ने पहले अपने एक आदेश में सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों को निर्देश दिया था कि वे 12 हफ्तों के भीतर सार्वजनिक स्थलों से अपने स्थायी झंडे के डंडे हटा लें। हाईकोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक स्थान जनता की संपत्ति हैं और उनका राजनीतिक या निजी उपयोग नहीं किया जा सकता। सीपीआई (एम) ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि पार्टी मजदूर वर्ग की अग्रणी संगठन है और झंडे जैसे प्रतीक उसके जनता से जुड़े रहने का माध्यम हैं। इसके साथ ही पार्टी का तर्क था कि हाईकोर्ट का यह आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन के अधिकार का उल्लंघन करता है और यह न्यायपालिका की तरफ से किया गया अनुचित कानून निर्माण है। अब सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ इस मामले की आगे की सुनवाई करेगी और यह तय करेगी कि हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा या उसमें बदलाव किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता को तेलंगाना उच न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और इस मामले को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और व्यवस्था का मजाक करार दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने नाराजगी जताते हुए कहा, मैं एक काम करूंगा, मैं यहां एक कॉलेजियम बैठक के लिए तीन वरिष्ठतम (उच न्यायालय) न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन करूंगा... आपने उच न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यावेदन और आवेदन करने के बारे में कहां सुना है? यह व्यवस्था का मजाक है! न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की भी पीठ, जीवी सरवन कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें उच न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि ऐसी याचिका कैसे दायर की जा सकती है। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को भी फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी याचिका अदालत के समक्ष कभी नहीं लाई जानी चाहिए थी। वकील ने खेद व्यक्त किया और याचिका वापस लेने की मांग की। इसके बाद याचिका वापस ली गई मानकर खारिज कर दी गई। उच न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के अलावा, याचिका में प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, लोकसभा में विपक्ष के नेता, सर्वोच न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और अन्य को पक्षकार बनाया गया था। उच न्यायालयों और सर्वोच न्यायालय में नियुक्तियां कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से संचालित होती हैं, जिसमें न्यायिक और पेशेवर साख के आधार पर न्यायाधीशों की सिफारिश की जाती है।

काश, सरदार पटेल होते!

रजेंद्र शर्मा

आज का दिन, हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे लिए तो विशेष गर्व का और आनंद का दिन है। आज हम अपने सरदार की जयंती मनाने के लिए यहां आए हैं। हमें इसका और भी आनंद है कि आज देशभक्तों की सरकार है, सरदार का आदर करने वालों की सरकार। आजादी के बाद एक समय था, जब सरदार का नाम लेने में लोग झिझकने लगे थे। सोचते थे कि कहीं मेरा नुकसान न हो जाए। राज करने वाले मुझसे नाराज न हो जाएं। मेरे यहां ईडी, सीबीआई के छापे न पड़ जाएं। मुझे मीसा-डीआईआर में जेल में न डाल दिया जाए। इतिहास की किताबों से सरदार गायब। बच्चों की किताबों से सरदार गायब। फिल्मों से सरदार गायब। सच पूछिए तो भारत के लोग तो करीब-करीब भूल ही गए थे कि कोई सरदार भी था। पर जब हमारी सरकार आयी, उसने आते ही सरदार के साथ अन्याय को मिटाने का बीड़ा उठाया। सरदार ही क्यों अन्य कितने ही भुला दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों की याद को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। और हमें गर्व है कि हमने सरदार का खोया सम्मान लौटाया, उनका गौरव किया, उनकी जयंती मनानी शुरू की। हमने जब उनकी विश्व की विशालतम प्रतिमा बनवाई, तब लोगों को पता चला सरदार के कद का, उनकी महानता का। हमने गर्व से कहा कि यह गर्व से कहने वालों की सरकार है कि हम सरदार के लोग हैं, और लोगों ने सरदार की महानता को पहचानना-समझना शुरू कर दिया। विरोधी कहेंगे कि सरदार के सम्मान में पहले भी कोई कसर नहीं थी, उनके जीते जी भी और मरने के बाद भी। सरदार के नाम पर अब क्या है, जो हमारे राज से पहले का नहीं है? राजधानी में संसद के ऐन बगल के चौराहे पर सरदार पटेल की प्रतिमा है। सरदार पटेल के नाम पर चौराहा है। सरदार पटेल भवन है। सरदार पटेल मार्ग भी है। यहां तक कि सरदार सरोवर बांध भी है। और तो और, अहमदाबाद का वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी सरदार पटेल के ही नाम पर था, जिसके जीर्णोद्धार करने के नाम पर, नाम ही बदलकर अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। पर ये सब हमारे यानी सरदार के विरोधियों की कहानीबाजियां हैं। किसी सड़क का नाम, किसी चौराहे का नाम, किसी भवन का नाम, संस्था का नाम, बांध का नाम या स्टेडियम का नाम रखने से, क्या सरदार के साथ हुआ अन्याय मिट सकता है? ये सब तो औरों के नाम पर भी हैं, फिर सरदार का विशेष गौरव करना क्या हुआ? और ये जो विरोधी अब कहीं से खोज लाए हैं कि नेहरू जी ने, सरदार पटेल के जीते जी उनकी किसी प्रतिमा का उद्घाटन किया था, यह अगर सच भी हो तो सरदार का गौरव करने की नहीं, असम्मान की बात है। उस प्रतिमा के लगने के बाद तो ऐसा लगता है कि सरदार की आयु और घट गयी थी। सचमुच दिल में सरदार का गौरव करना होता, तो नेहरू जी भी तो सरदार की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवा सकते थे, उन्हें किसने रोका था क्या? मेरे परिवारजनो, आपके आशीर्वाद से और आपके इस सेवक के विनम्र प्रयासों से, अब सारी दुनिया हमारे सरदार को पहचानने लगी है। सचमुच सारी दुनिया क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वह भी सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। यानी मोदी के नाम के साथ, सरदार का नाम भी दुनिया भर में जा रहा है। फिर भी, हमारे मन में एक कसक अब भी है। काश, सरदार हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री होते। सिर्फ गृहमंत्री ही क्यों हुए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं? हमें तो गांधी जी से भी शिकायत है कि ये एक काम गांधी जी ने अच्छा नहीं किया। उन्हें नेहरू की अरबन नक्सल टाइप की बातों में नहीं आना चाहिए था और सरदार को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए था? आखिरकार, नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने से सब का नुकसान ही हुआ, खुद गांधी जी का भी। अगर सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री होते, तो क्या गांधी जी को गोली लगती? कभी नहीं। न गोडसे को गांधी जी से शिकायत होती और न गांधी जी को बिड़ला हाउस में गोली लगती। एक नहीं दो-दो जानें तो यूं ही बच जातीं। गांधी जी की भी और गोडसे जी की भी। और जाहिर है कि सावरकर जैसी महान आत्मा को, गांधी की हत्या के आरोपों की बदनामी तो नहीं ही झेलनी पड़ती। और हां! आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने, संघ के नेताओं व कार्यकर्ताओं को जेल में डाले जाने, आदि का भी कोई प्रसंग नहीं आता। और तब आरएसएस को भी प्रतिबंध हटवाने के लिए सरदार से यह कच्चा वादा नहीं करना पड़ता कि वह राजनीति से दूर रहेगी! और हां! प्रतिबंध के प्रसंग से याद आया, सरदार अगर प्रधानमंत्री होते, तो क्या आरएसएस पर प्रतिबंध लगने देते? सरदार के विरोधी, उन्हें यह कहकर झूठा बदनाम करते हैं कि आरएसएस पर प्रतिबंध तो उन्होंने ही लगाया था और वह भी अपनी कलम से। असल में आरएसएस पर सरदार से प्रतिबंध लगवाना तो, उन्हें बदनाम करने की नेहरू की चाल थी। चूंकि नेहरू प्रधानमंत्री थे, गृहमंत्री के नाते सरदार उनका फैसला लागू करने के लिए बाध्य थे और वह भी तब उनके बीच फैसला कराने वाले गांधी जी जा चुके थे। पर सरदार ने वह फैसला जरूर बहुत भारी मन से लिया था। वैसे ही जैसे उन्होंने कश्मीर की धारा-370 का फैसला बहुत भारी मन से लिया था। हमें तो लगता है कि गृहमंत्री ही रह जाने की विवशता में लिए गए ऐसे कतिपय निर्णयों का ही दुख था, जिससे सरदार बीमार रहने लगे थे और कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु भी हो गयी, हालांकि जाने से पहले वह अपनी कलम से आरएसएस को प्रतिबंध-मुक्त कर गए। बहनो, भाइयो, सरदार तब प्रधानमंत्री होते, तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता। धारा-370 न कभी होती और न हमारे छोटे सरदार को सत्तर साल बाद उसे खत्म करना पड़ता। अगर सरदार होते, तो सिक्किम तो सिक्किम, तिब्बत भी भारत का हिस्सा होता। अगर सरदार होते तो, बांग्लादेश नहीं बनता, पूरा बंगाल हमारा होता, पूरे कश्मीर की तरह। बंगलादेश ही नहीं होता, तो घुसपैठियों की समस्या भी नहीं होती। अगर सरदार होते तो, हम अखंड भारत...।

वादे और दावे के बीच झूलती बिहार की राजनीति

बिहार में चुनावी घमासान की हवा चल रही है। प्रमुख राजनीतिक दल इस हवा के रुख को अपनी ओर मोड़ने का जी तोड़ प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई भी ऐसी आधारित पौलिसित नहीं हो रही है कि हवा किस ओर बह रही है। राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे दावे और वादे सत्ता की राह को आसान बनाने की मात्र कवायद ही कही जा सकती है। बिहार की राजनीति में चार प्रमुख राजनीतिक दल जोर लगा रहे हैं, बाकी के सभी इनके सहारे सत्ता का स्वाद चखने के लिए लालायित हैं। यह प्रमुख दल अपने ही दल के अंदर उठ रहे भीतरघात के लावे से परेशान हैं। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल की बात है तो उनके घर के अंदर से ही विरोध की चिंगारी सुलग रही है। जो भविष्य में बड़ी आग का रूप भी ले सकती है। तेजप्रताप यादव नए दल के साथ चुनावी मैदान में उतरकर तेजस्वी के सपनों को मिटाने का अभियान छेड़े हुए हैं, वहीं उनके पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के शासन करने का अंदाज एक बड़ी चुनौती बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से इसी को चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार को विकास चाहिए या फिर जंगलराज चाहिए। लालू प्रसाद यादव के शासन बारे में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से इस आशय की टिप्पणी की गई थी कि बिहार में जंगलराज है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अपनी सरकार के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए राजद के पास केवल भाजपा का विरोध करना ही प्रचार करने का एक मात्र विकल्प है। यह वोट प्राप्त करने का माध्यम तो बन सकता है, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से नकारात्मक राजनीति का पर्याय ही माना जाएगा। नकारात्मक राजनीति किसी भी प्रकार से उचित नहीं मानी जा सकती। बिहार की राजनीति में वोट चोरी का मामला भी जोर शोर से उठाया गया। इसका लाभ भी विपक्ष उठा सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को उठाने में विपक्ष ने जल्दबाजी कर दी। चुनाव आयोग की ओर से वोट चोरी के बारे में पक्ष रखने के बाद यह मुद्दा गहरी खाई में समा गया। कांग्रेस और राजद की ओर से जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है, वह यही संकेत करती है कि इनको सत्ता प्राप्त करने की जल्दी है। हमारे देश में एक कहावत तो सबने सुनी ही होगी कि जल्दी फायदा कम, नुकसान ज्यादा करती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती का परिणाम सभी देख चुके हैं। अब बिहार में राहुल और तेजस्वी एक साथ हैं। राजनीतिक वातावरण में हमेशा से यही प्रचलित धारणा बनी हुई है कि दुश्मन का दुश्मन भी एक दोस्त की तरह ही होता है। कांग्रेस, भाजपा को राजनीतिक विरोधी ही मानती है, इसके साथ ही राजद के विचार भी भाजपा के विपरीत ही हैं। इसलिए बिहार में आज कांग्रेस और राजद एक साथ हैं। विपक्ष की ओर से राजद के नेता तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया है। उन पर परिवारवाद की राजनीति का तमगा भी लगा है। इसके कारण भी राजद के अन्य वरिष्ठ नेता मैदान में खुलकर नहीं आ रहे हैं।

राजद के कई नेताओं का अंदाज तेज प्रताप को समर्थन देने जैसा ही है। इस प्रकार की राजनीति भितरघात की श्रेणी में आएगी। अगर बिहार में तेजप्रताप अपना राजनीतिक कौशल दिखा पाते हैं तो यह स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है कि फिर तेजस्वी की राह कांटों भरी ही होगी। दोनों भाइयों के बीच यह राजनीतिक घमासान मात्र नेतृत्व की ही लड़ाई है। यह भी सबको समझ में आ रहा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का चुनावी मैदान में आना राजनीतिक सौदेबाजी करने जैसा ही माना जा रहा है। प्रशांत किशोर जितना जोर दिखाएंगे, उतना ही वह बिहार की राजनीति को प्रभावित करेंगे। यह प्रभाव किसके लिए खतरा बनेगा, यह अभी से कह पाना संभव नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति स्थिति को देखकर यही कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का फोकस उन वोटों पर अधिक है, जो राजद या कांग्रेस को मिलते हैं। कर्पूरी ठाकुर के परिजन को अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाना भी संभवतः इसी रणनीति का ही हिस्सा है। जहां तक भाजपा और नीतीश कुमार की जदयू की बात है तो यही कहा जा सकता है कि यह दोनों ही विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार को विकास की जरूरत भी है। भाजपा और जदयू को लगता है कि विकास के नाम पर उसे फिर से सत्ता प्राप्त हो जाएगी। इसके विपरीत विपक्ष की ओर से कांग्रेस और राजद की ओर से आम जन के निजी स्वार्थों को कुरेदकर उनको आर्थिक लाभ देने के वादे किए जा रहे हैं। ऐसे वादे लोग को त्वरित लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। नौकरियां देना भी असंभव है, इसलिए स्वरोजगार देने का प्रयास करना चाहिए। केन्द्र सरकार इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। जिसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। कई लोगों ने अपना जीवन स्तर भी सुधारा है। युवाओं को नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। बिहार के युवा इस बारे में सोचें, यही बिहार की राजनीति का आधार बने। राजनीतिक दलों को इस बारे में भी सोचना चाहिए। राजनीति को जन भावनाओं के अनुसार ही होना चाहिए। इसके लिए परिवारवाद नहीं, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए हर राजनीतिक दल को प्रयास करना चाहिए। हालांकि हमारा आशय परिवार के सहारे राजनीति में कदम रखने वाले राहुल और तेजस्वी के राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल खड़े करने का नहीं है। हो सकता है कि वे देश की भावी राजनीति के सूत्रधार बनें, लेकिन फिलहाल उनके खाते में ऐसी कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है, जिसके आधार पर उनका राजनीतिक आकलन किया जाए। विपक्ष की दूसरी कठिनाई यह है कि इनके पास प्रचार करने वाले जमीनी नेताओं की कमी है, जबकि भाजपा और जदयू में ऐसे नेताओं की लम्बी सूची है। जिसके कारण यह सभी जगह अपना प्रचार करने की योजना बना सकते हैं। अब देखना यह है कि बिहार की जनता किसको पसंद करेगी और किसको नापसंद, यह आने वाले समय में पता चल जाएगा।

चुनावी मौसम में पत्रकारों का कर्त्तव्य

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता है और इस जनता की आवाज बनने का दायित्व पत्रकारों पर है। चुनाव वह समय होता है जब यह शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है, जब जनता अपने मत से आने वाले पांच वर्षों की दिशा तय करती है। ऐसे निर्णायक समय में मीडिया की भूमिका केवल सूचना देने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह एक प्रहरी यानी 'वॉचडॉग' की भूमिका निभाता है। दुर्भाग्य से आज के परिदृश्य में कई बार यह प्रहरी सार्वजनिक हित का रक्षक बनने के बजाय सत्ता या किसी दल का प्रचारक बनता दिखता है। यही वह विमर्श है जिस पर विचार होना चाहिए कि पत्रकारों और एंकरों को क्यों और कैसे अपनी मूल भूमिका निभानी चाहिए, न कि पीआर (पब्लिक रिलेशन) पेशेवर बन जाना चाहिए। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य हमेशा सत्य का अन्वेषण रहा है। पत्रकार न तो किसी नेता के समर्थक होते हैं, न विरोधी, वे केवल जनता के प्रतिनिधि हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रेस का काम जनता को सरकार की भूलों से सतर्क करना है, सरकार का मुखपत्र बनना नहीं। जब चुनाव आते हैं तो यही भूमिका और भी संवेदनशील हो जाती है क्योंकि इस समय जनता को सूचित निर्णय लेने के लिए निष्पक्ष जानकारी चाहिए होती है। यदि मीडिया इस समय भ्रम फैलाए या किसी पक्ष के प्रचार का माध्यम बने तो लोकतंत्र की आत्मा को आघात पहुंचता है। पत्रकारिता एक सार्वजनिक सेवा है, जबकि पीआर एक निजी हित का कारोबार। दोनों के स्वरूप में मूलभूत अंतर है। जहां पत्रकारिता का उद्देश्य सत्य और पारदर्शिता है, वहीं पीआर का उद्देश्य छवि निर्माण होता है और वह भी किसी व्यक्ति या संगठन के हित में। जब कोई पत्रकार या एंकर अपने मंच का उपयोग किसी नेता की छवि चमकाने या विरोधी को बदनाम करने के लिए करता है तो वह पत्रकार नहीं, पीआर एजेंट बन जाता है। यह स्थिति न केवल उसकी पेशेवर आचार संहिता का उल्लंघन करती है, बल्कि जनता के साथ विश्वासघात भी है। चुनाव कवरेज अक्सर टीआरपी की होड़ में सनसनीखेज रूप ले लेता है लेकिन वास्तविक पत्रकारिता की परीक्षा इसी समय होती है जब दबाव हो, आकर्षण हो और फिर भी कोई पत्रकार निष्पक्ष रह पाए। पत्रकारों को चाहिए कि वे चुनावी खबरों में तथ्यों की पुष्टि करें, उम्मीदवारों के वादों की जांच करें और जनता से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखें, न कि केवल रैलियों की भीड़ या विवादों की गहमागहमी को। एंकरों के लिए भी यह समय आत्म-संयम का होता है। उनसे अपेक्षा है कि वे मंच पर दोनों पक्षों को बराबर अवसर दें, तर्क पर तर्क से जवाब लें और चुनावी बहस को 'शोर' नहीं बल्कि 'संवाद' में बदलें। पत्रकारों व एंकरों का उद्देश्य दर्शकों को किसी दल की मनोवैज्ञानिक दिशा में मोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। लोकतंत्र में पत्रकार सत्ता का संतुलन बनाए रखने वाले चौथे स्तंभ का प्रतिनिधि है। चुनाव काल में जब राजनीतिक दल वादों की बाढ़ लाते हैं तब मीडिया का दायित्व है कि वह इन वादों की जांच करे। कौन से वादे व्यावहारिक हैं, कौन से केवल भाषणों की सजावट। इसके अलावा मीडिया को यह भी देखना चाहिए कि क्या चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी है? क्या प्रशासन और चुनाव आयोग निष्पक्ष है?

क्या मतदाता को स्वतंत्र रूप से वोट डालने का अवसर मिल रहा है? यदि पत्रकार यह निगरानी न करें तो सत्ता और धनबल का उपयोग करके जनमत को गुमराह करने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में पत्रकार ही वह दीवार है जो जनतंत्र को 'विज्ञापनतंत्र' बनने से बचा सकती है। सच्चा पत्रकार अपनी राय जरूर रख सकता है लेकिन उसे तथ्यों की सत्यता से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह हर रिपोर्ट में स्रोत स्पष्ट करे, हर दावा परखे और किसी भी राजनीतिक संदेश को प्रसारित करने से पहले उसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करे। पत्रकारिता में 'निष्पक्षता' का अर्थ यह नहीं कि सबकी बात एक समान मानी जाए, बल्कि यह कि सच्चाई के प्रति जवाबदेही रखी जाए, चाहे वह सत्ता के खिलाफ हो या विपक्ष के। एंकरों को भी समझना होगा कि उनका मंच और चैनल एक भरोसे का प्रतीक है। यदि वे उसी मंच से किसी विशेष पार्टी के प्रवक्ता बन जाएं तो वह भरोसा टूट जाता है। ट्रोल्स के प्रभाव, कॉर्पोरेट दबाव और राजनीतिक समीकरणों के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन अवश्य है, पर यही कठिनाई पत्रकारिता को सम्मान दिलाती है। आज के युग में सोशल मीडिया ने सूचना का लोकतंत्रीकरण किया है लेकिन अफवाहों और आधी सच्चाइयों के प्रसार का खतरा भी बढ़ा है। इस वातावरण में टीवी और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्हें चाहिए कि वे त्वरित सुर्खियों से आगे बढ़कर पड़ताल करें, डेटा और दस्तावेजों पर आधारित रिपोर्ट तैयार करें और जनता को यह सिखाएं कि सच्ची खबर कैसे पहचानी जाए। यदि पत्रकार भी सिर्फ ट्रेंड या वायरल वीडियो के पीछे भागने लगे तो वह समाज को जागरूक नहीं बल्कि भ्रमित करेगा। आज चुनाव के मौसम में पत्रकारों को आत्ममंथन की जरूरत है। क्या वे अपनी रिपोर्टों से जनता को सशक्त बना रहे हैं या किसी राजनीतिक पार्टी या कॉर्पोरेट घराने के एजेंडे को मजबूत कर रहे हैं? क्या उनके सवाल जनता के प्रश्न हैं या टीआरपी के लिए रचे गए नाटक? लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब पत्रकार अपने पेशे की आत्मा को जिंदा रखेंगे।

जब वे सत्ता से नहीं, बल्कि जनता से डरेंगे। 'वॉचडॉग' बनने का अर्थ है सत्ता पर निगाह रखना, अन्याय पर सवाल करना और जनता के अधिकारों की रक्षा करना। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या नगरपालिका का, मीडिया का धर्म एक ही है- सच दिखाना, पूरी ईमानदारी से, चाहे किसी को असुविधा ही क्यों न हो। पत्रकारिता केवल करियर नहीं, बल्कि लोकसेवा का माध्यम है। यदि पत्रकार और एंकर इस आत्मा को पहचान लें और चुनावी मौसम में पीआर के प्रभाव से ऊपर उठकर तटस्थ प्रहरी बनें तो लोकतंत्र की नींव और अधिक मजबूत होगी। जनमत जागरूक होगा, सत्ता जवाबदेह बनेगी और भारत की लोकतांत्रिक परंपरा सच्चे अर्थों में सशक्त होगी।

भाजपा से समन्वय की जिम्मेदारी अब अतुल लिमए को ?

पिछले काफी समय से भाजपा व संघ के रिश्ते सांप-सीढ़ी का खेल खेलते आए हैं, पर संघ का शीर्ष नेतृत्व भाजपा संग एक बेहतर समन्वय चाहता है। जिसके लिए आने वाले दिनों में संघ में एक बड़ा सांगठनिक बदलाव देखा जा सकता है। संघ से जुड़े विश्वस्त सूत्र खुलासा करते हैं कि भाजपा के संग एक बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए संघ अरुण कुमार की जगह अतुल लिमए को ला सकता है। इस बात के इशारे इस 30 अक्तूबर से शुरू हुई संघ की जबलपुर में आहूत त्रिदिवसीय बैठक में मिले। स्मरण रहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की तीन दिवसीय बैठक इन दिनों जबलपुर की कचनार सिटी में जारी है। इस बैठक में 11 क्षेत्रों व 46 प्रांतों के संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक और निमंत्रित कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में संघ के सभी 6 सहकार्यवाह यानी डा. कृष्ण गोपाल, मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त जी चक्रधर, आलोक कुमार और अतुल लिमए भी जुटे हैं। सूत्रों की मानें तो संघ का शीर्ष नेतृत्व अरुण कुमार की जगह अतुल लिमए को लाने का मन बना चुका है। अभी अरुण कुमार ही संघ और भाजपा के बीच एक संवाद सेतु का काम करते हैं। महाराष्ट्र के नासिक से ताल्लुक रखने वाले 54 वर्षीय अतुल लिमए जो जाति से एक चितपावन ब्राह्मण हैं वे इस महाराष्ट्र चुनाव से चर्चा में आए। कहते हैं राज्य में भाजपा गठबंधन को सत्ता में लाने में लिमए की एक महती भूमिका रही। वह पेशे से एक इंजीनियर हैं और कोई 3 दशक पूर्व संघ से एक पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर जुड़े। इनकी महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा जैसे राज्यों पर गहरी पकड़ है। कहते हैं इन्होंने इस मुश्किल का रामबाण ढूंढा कि 'अर्बन नक्सल' और 'मराठा आंदोलन' से कैसे निबटा जाए। इन्होंने संघ के लिए कई 'थिंक टैंक भी तैयार किए हैं और कई 'रिसर्च टीम' भी बनाई हैं। संघ का बेहद चर्चित रहा 'सजग रहो' कैंपेन का प्रणेता भी इन्हीं को बताया जाता है। कई शैक्षणिक व राजनीतिक सरकारी पदों पर प्रमुखों की नियुक्तियों को भी ये प्रभावित करते रहे हैं, चूंकि आने वाले दिनों में भाजपा संगठन का पूरी तरह कायाकल्प होना है सो, उसकी पूर्व बेला में भाजपा से समन्वय की कमान पूरी तरह लिए के हाथों में सौंप सकते हैं। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने भले ही पिछले कुछ समय से अपरोक्ष तौर पर भगवा राग गाना शुरू कर दिया हो, पर इसका उन्हें कोई खास फायदा मिलता नहीं दिख रहा। उनके सांसद पुत्र कार्ति चिदंबरम पर ईडी की तलवार बदस्तूर पहले की तरह ही लटक रही है। कार्ति ने ईडी द्वारा 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत जब्त की गई अपनी संपत्तियों को लेकर 'एपीलिएट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरफिटेड प्रापर्टी' में एक अपील दायर की थी, जिसे अभी ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया है। बेहद भरोसेमंद सूत्रों का दावा है कि पिता चिदंबरम इस मुश्किल घड़ी में अपने बेटे के साथ साए की तरह खड़े रहे और उन्हें कुछ फौरी निजात दिलाने के लिए सरकार के एक सर्वशक्तिमान मंत्री जी को लगातार फोन करते रहे, पर कहते हैं मंत्री जी लाइन पर ही नहीं आए। उनके यहां से चिदंबरम साहब को बता दिया गया कि मंत्री जी बिहार चुनाव में बहुत बिज़ी हैं, अभी उनसे बात नहीं हो पाएगी, वे चाहें तो अपना मैसेज छोड़ सकते हैं।

मीठीबाई का फिनांज़ा'26 - नवाचार, विचार और अनंत संभावनाओं की नई उड़ान!

मुंबई (अशोका एक्सप्रेस)मीठीबाई कॉलेज का बहुप्रतीक्षित फिनांज़ा'26 का भव्य शुभारंभ मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में हुआ। यह लॉन्च डे सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि मुंबई के सबसे तेज़ी से बढ़ते फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट की नई शुरुआत थी। हर साल की तरह इस बार भी फिनांज़ा ने अपनी विशालता, दृष्टि और उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों के साथ सभी का दिल जीत लिया।

अब अपने 9वें संस्करण में प्रवेश कर चुका फिनांज़ा आज एक बड़ा समुदाय बन चुका है - 100 से ज्यादा कॉलेज, 30,000 फाइनेंस और बिज़नेस प्रेमी, और 350 जोश से भरे छात्र आयोजक इसका हिस्सा हैं।

वर्षों से यह उत्सव रचनात्मकता, सीख और नेतृत्व का प्रतीक बन गया है। फाइनेंशियल और एंटरप्रेन्योरियल समिट्स, रंगीन [illegible] कार्निवल, और प्रेरणादायक Fables with Finanza जैसे कार्यक्रमों ने इसकी पहचान को और भी मज़बूत किया है।

16 सितंबर को लॉन्च डे के साथ फिनांज़ा'26 ने अपनी इस नई यात्रा की शुरुआत की, एक ऐसी यात्रा जो इस साल के सबसे दूरदर्शी संस्करण की झलक दिखाती है।

इस साल की थीम Into the Finverse" है - यानी फिनवर्स में कदम रखना। यह थीम असीम खोज, सीख और कल्पना की भावना को दर्शाती है। यहाँ वित्तीय ज्ञान और उद्यमशील सोच मिलकर

एक ऐसा ब्रह्मांड बनाते हैं जहाँ विचारों की कोई सीमा नहीं और सपनों की कोई रुकावट नहीं।

जैसे ब्रह्मांड हर पल फैल रहा है, वैसे ही फिनवर्स भी लगातार बढ़ने और सीखने का प्रतीक है - जहाँ आसमान कोई सीमा नहीं, बल्कि बस शुरुआत है!

कार्यक्रम की शुरुआत एक शानदार CXO पैनल चर्चा से हुई। मंच पर मौजूद थे -

श्री विनोद हेझमादी (पूर्व [illegible], एयर इंडिया),

श्री मयुरेश कोरे (CFO, इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड),

श्री अखिल चतुर्वेदी (CBO, मोतीलाल ओसवाल) और

श्री संदीप मिश्रा (CDO, आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस)।

सत्र का संचालन ET No2 की सीनियर एंकर सुश्री अनीशा जैन ने किया।

हर वक्ता ने अपने अनुभवों से श्रोताओं को प्रेरित किया।

श्री हेझमादी ने विमानन क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कठिन समय में नैतिक फैसले और दृढ़ता सबसे बड़ी ताकत होती है।

श्री कोरे ने मनोरंजन क्षेत्र में रचनात्मकता और वित्तीय प्रबंधन के संतुलन की बात की।

श्री चतुर्वेदी ने निवेश के क्षेत्र में धैर्य और अनुशासन को सफलता की कुंजी बताया, जबकि श्री मिश्रा ने वित्तीय सेवाओं में टेक्नोलॉजी और डिजिटल बदलाव की भूमिका समझाई।

इन सभी विचारों ने छात्रों को नेतृत्व, नवाचार और जिम्मेदारी की गहरी समझ दी।

इसके बाद मंच संभाला श्री पंकज गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, गोदरेज फाइनेंस ने।

उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कैसे वित्तीय दुनिया को नई दिशा दे रही है।

उन्होंने कहा कि तकनीकी नवाचार तभी सार्थक है जब वह उद्देश्य और मानवीय मूल्यों से जुड़ा हो।

उनका भाषण छात्रों के लिए प्रेरणा और भविष्य की सोच से भरपूर था।

कार्यक्रम का सबसे रंगीन हिस्सा था Under 25 Summit, जिसे ज़ेरोधा ने प्रस्तुत किया।

यह सत्र रचनात्मकता, बातचीत और संस्कृति का अनोखा संगम था।

कॉमेडियन जितेश चसानी ने सबको हँसी से लोटपोट कर दिया, जबकि कौस्तुभ कुलकर्णी, Under 25 के स्टूडेंट कम्युनिटी हेड - ने युवाओं से अपने अनुभव साझा किए।

मॉडल और अभिनेत्री अदिति शेट्टी ने अपने करियर की प्रेरक कहानी बताई, और अंत में अभिनेत्री प्रतिभा रांटा, जिन्हें लापता लेडीज़ और हीरामंडी में उनके शानदार अभिनय के लिए जाना जाता है, ने अपने संघर्ष और जुनून से दर्शकों को प्रेरित किया।

इस सत्र ने पूरे ऑडिटोरियम में जोश और उमंग भर दी।

लेकिन फिनवर्स की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती।

फिनांज़ा'26 अब अपने अगले रोमांचक अध्याय की ओर बढ़ रहा है Fables with Finanza", जहाँ उद्योग जगत की बड़ी हस्तियाँ अपनी कहानियाँ और अनुभव साझा करेंगी।

यह सत्र सिर्फ वित्तीय ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन और नेतृत्व से जुड़ी प्रेरणाएँ भी देगा।

फिनांज़ा का मकसद है, वित्त को मज़ेदार, समझने में आसान और सबके लिए सुलभ बनाना।

यह सिर्फ एक फेस्ट नहीं, बल्कि एक छात्र आंदोलन है, छात्रों द्वारा, छात्रों के लिए, जो जिज्ञासा, सीख और नवाचार की भावना से आगे बढ़ता है।

फिनवर्स अभी शुरू हुआ है, और इसका ब्रह्मांड अब और भी बड़ा होने वाला है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वरुण ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया संपादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/08862)

कम उपस्थिति के कारण विधि पाठ्यक्रम के किसी छात्र को परीक्षा देने से न रोका जाए: दिल्ली उच्च न्यायालय

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को व्यवस्था दी कि देश में विधि पाठ्यक्रम के किसी भी छात्र को न्यूनतम उपस्थिति न होने के कारण परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता। उच्च न्यायालय ने विधि महाविद्यालयों में अनिवार्य उपस्थिति की आवश्यकता से संबंधित कई निर्देश जारी करते हुए बार कार्उंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को उपस्थिति मानकों में बदलाव करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि कम उपस्थिति के कारण छात्र को परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति शर्मा की पीठ ने यह आदेश स्वत संज्ञान याचिका का निपटारा करते हुए दिया। 2016 में विधि के छात्र सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह याचिका शुरू की थी। रोहिल्ला ने कथित तौर पर आवश्यक उपस्थिति न होने के कारण सेमेस्टर परीक्षा देने से रोके जाने के बाद अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। पीठ ने कहा, सभी पक्षों की दलीलों और सामने आई वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए अदालत का मानना है कि सामान्य शिक्षा और विशेष रूप से विधि शिक्षा में ऐसे कठोर नियम नहीं होने चाहिए, जिनसे छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो। सुशांत रोहिल्ला एमिटी विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष के छात्र थे। उन्होंने 10 अगस्त 2016 को आत्महत्या की थी। बताया जाता है कि उन्हें कथित तौर पर आवश्यक उपस्थिति न होने के कारण सेमेस्टर परीक्षा देने से रोक दिया गया था। रोहिल्ला ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वे निराश महसूस कर रहे हैं और जीवित नहीं रहना चाहते।

पूर्वी दिल्ली में एनआरआई महिला का बैग छीनने वाले दो व्यक्ति पकड़े गए

नई दिल्ली । पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एनआरआई (अप्रवासी भारतीय) वरिष्ठ नागरिक से हैंडबैग छीनने के आरोप में पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान 26 वर्षीय रोहित और मुकुल (24) के तौर पर हुई है और उन्होंने 28 अक्टूबर को ब्रिटेन से आई महिला को निशाना बनाया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, जब वह पैदल जा रही थीं, तो दोनों मोटरसाइकिल पर आए और उनका हैंडबैग छीनकर भाग गए। अधिकारी ने कहा, अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, सोने के आभूषण, 135 पाउंड (ब्रिटेन की मुद्रा), पीड़िता का मोबाइल फोन, पर्स, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज उनके कब्जे से बरामद किए गए। मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई। अधिकारी ने बताया कि 15 किलोमीटर के मार्ग पर लगे 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को फुटेज खंगाली गई और फिर मुखबिर की सूचना पर दोनों को पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जुर्म कबूल करते हुए कहा कि वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उन्होंने महिला को निशाना बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि वह एनआरआई है और उसके पास संभवतः कीमती सामान है।

ओआरएस ब्रांडिंग वाले पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की आदेश के खिलाफ याचिका

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है जिसमें किसी भी फल-आधारित, गैर-कार्बोनेटेड या रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थ पर ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ओआरएस) लेबलिंग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि एफएसएसएआई द्वारा उठाए गए कदम गंभीर जन स्वास्थ्य चिंताओं से प्रेरित हैं और ये पूरे खाद्य उद्योग पर लागू होने वाले नियामक उपाय हैं। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने 31 अक्टूबर को पारित एक आदेश में एफएसएसएआई के 14 और 15 अक्टूबर के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उन न्यायालय ने कहा कि इन परिस्थितियों में यह न्यायालय एफएसएसएआई द्वारा 30 अक्टूबर, 2025 को पारित आदेश में विवादित आदेशों पर रोक लगाने के लिए इच्छुक नहीं है। यह विशेष रूप से ओआरएस फॉर्मूलेशन की चिकित्सीय आवश्यकता वाले लोगों द्वारा आपत्तिजनक उत्पादों के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों और प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों के मद्देनजर है। अदालत ने आगे कहा कि न्यायालय को जन स्वास्थ्य के मद्देनजर एफएसएसएआई द्वारा उठाए गए कदम पर अपील करना उचित नहीं लगता। अदालत ने डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एफएसएसएआई के उस निर्देश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसके ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ब्रांड रेक्लान्ज़ विटर्स के लिए ओआरएस लेबल के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था। कार्यवाही के दौरान, फार्मा कंपनी के वकील ने बयान दिया कि याचिकाकर्ता ने अपने उत्पादों के नए स्टॉक का निर्माण बंद कर दिया है। दरअसल 14 अक्टूबर को एफएसएसएआई ने एक आदेश जारी कर खाद्य और पेय पदार्थ कंपनियों को उत्पाद के नाम या ब्रांडिंग में ओआरएस शब्द के उपयोग की सभी पूर्व अनुमतियां वापस ले लीं जब तक कि वे मानक चिकित्सा फॉर्मूलेशन को पूरा न करें। खाद्य सुरक्षा नियामक ने शर्करायुक्त या इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय पदार्थों की ब्रांडिंग में ओआरएस के इस्तेमाल को उपभोक्ताओं, खासकर बच्चों के लिए भ्रामक और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन माना है।

किराए के भवन से बाहर आएंगे 18 थाने, पुलिस को मिलेंगी अपनी इमारतें; 653 करोड़ खर्च होंगे निर्माण में

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस के 18 पुलिस थानों को जल्द ही अपनी बिल्डिंग होगी। इसके लिए जमीन मिल गई है और केंद्रीय गृहमंत्रालय ने भवन बनाने की अनुमति भी दे दी है। थानों के लिए बिल्डिंग बनाने में कुल 653 करोड़ होंगे खर्च होंगे। परियोजना पूरा करने का जिम्मा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (सीपीडब्ल्यूडी) को दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने हाल ही में पुलिस के 26 प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 18 पुलिस थानों को बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 653.46 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति और खर्च की मंजूरी दी है। इनमें से कुछ थानों की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है तो कुछ किराए की इमारत में चल रहे हैं। जैतपुर थाना इनमें सबसे महंगा है लेकिन अन्य थानों का भी किराया लाखों में है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 18 पुलिस स्टेशनों की बिल्डिंग के अलावा इस रकम से पुलिस को सात नई चौकियां भी बनाई जाएंगी। ये चौकियां किराए के मकानों में चल रही है। इसी तरह रोहिणी में महिला स्टाफ के लिए एक वूमेन हॉस्टल बनाया जाएगा, जो सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। पुलिसकर्मियों को बेहतर आवास की सुविधाओं के मद्देनजर 15 पुलिस स्टेशन के परिसरों में कुल 180 फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जिनमें हर कॉम्प्लेक्स में 12-12 फ्लैट्स बनाने की योजना है। कई अन्य छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स भी है, जिन्हें इस रकम के जरिए पूरा करने में मदद मिलेगी। किराए की इमारतों में चल रहे पुलिस स्टेशन की वजह दिल्ली में जमीन की कमी बताई जा रही है। इसकी वजह से दिल्ली पुलिस पर मासिक खर्च बढ़ता है। स्टेशनों की बुनियादी ढांचागत स्थिति भी प्रभावित होती है। कई स्टेशनों के लिए सरकार नई इमारतें बनाने की योजना बना रही है। भरत नगर, शाहबाद डेरी, प्रेम नगर, स्वरूप नगर, भलस्वा डेरी, जैतपुर, सोनिया विहार, फतेहपुर बेरी, छावला, करावल नगर, निहाल विहार, रणहौला और तिगड़ी थाने किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं।

सख्ती से निपटा जाएगा, 3 हजार करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (03 नवंबर, 2025) को डिजिटल अरेस्ट से सख्ती से निपटने की बात कही है। इन मामलों में साहूकार क्रिमिनल लोगों को नकली सरकारी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी या फिर जांच अधिकारी बनकर खासकर बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं और पैसे ऐंठते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ितों से लगभग 3 हजार करोड़ रुपये वसूले गए हैं और यह समस्या आगे बढ़ने वाली है। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को सुनेगा और एक न्यायमित्र, वरिष्ठ वकील एनएस नप्पिन्नई की नियुक्ति करेगा। मामले पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, यह चौंकाने वाला मामला है कि अकेले हमारे देश में पीड़ितों से लगभग 3,000 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। अगर हम इसे अभी नजरंदाज करते हैं और कड़े और सख्त आदेश पारित नहीं करते हैं तो समस्या और बढ़ जाएगी। हम इससे सख्ती से निपटने का पक्का इरादा रखते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सबसे दुखद बात यह है कि पीड़ित खासकर बुजुर्ग लोग हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि गृह मंत्रालय में एक स्पेशल यूनिट है जो ऐसी शिकायतों की जांच कर रही है। उन्होंने विस्तारित रिपोर्ट फाइल करने के लिए समय की मांग की।

नई दिल्ली . किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी ने सुल्तानपुरी के जलेबी चौक पर प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए मास्क वितरण व, विरोध प्रदर्शन, जिला महासचिव, विजय कुमार भारती, राहुल और वरुण ढक्का, रियाज़ खान, नबी बख्श ठेकेदार, ओम प्रकाश राठौर, सुलेमान सलमानी ,मुकेश राणा, प्रदीप कुमार (घांसु), सोनू प्रधान ,पंकज अग्रवाल, वार्ड,42,43,44 के ब्लॉक अध्यक्ष, प्रमोद पंचल, दीपक चुन्नीलाल, चंदन सिंह, सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए . छाया = आकाश शक्य

हरियाणा राइट टू सर्विस आयोग ने औसत बिलिंग मामले में उपभोक्ता को 5 हजार रुपये मुआवज़ा देने के दिए निर्देश

चंडीगढ़ ।

हरियाणा राइट टू सर्विस आयोग ने एक उपभोक्ता को पाँच वर्ष से अधिक समय तक औसत आधार पर बिल जारी किए जाने के मामले में गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने कहा है कि यह अत्यंत खेदजनक है कि इतने लंबे समय तक उपभोक्ता को वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिल नहीं दिया गया और यह मामला निगमों की समीक्षा प्रणाली से बचा रहा। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने पाया कि यह कोई एकमात्र मामला नहीं है, बल्कि इस प्रकार की शिकायतों पर पूर्व में भी अनेक बार निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आयोग ने अपने पूर्व आदेश में दोनों निगमों के प्रबंध निदेशकों को इस प्रकार के लंबे समय तक औसत बिल जारी होने वाले मामलों में सहत या वसूली नीति तैयार करने के निर्देश दिए थे। आयोग ने टिप्पणी की कि जब पर्याप्त निगरानी और प्रणाली उपलब्ध हैं, तब भी उपभोक्ताओं को वर्षों तक औसत बिल पर चार्ज करना निगम की साख को धूमिल करता है। आयोग ने यह भी माना कि उपभोक्ता वास्तविक खपत के आधार पर भुगतान करने का उत्तरदायी है, किंतु वर्षों तक नियमित बिल मिलने के बाद एक साथ भारी राशि का बिल जारी करना अनुचित है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार, उपभोक्ता के अंतिम रीडिंग वास्तविक खपत पर आधारित हैं जिनका भुगतान उसे करना होगा। हालांकि, लैब रिपोर्ट में मीटर के जानबूझकर जलाने का आरोप लगाया गया है, जिस पर आयोग ने टिप्पणी करने से परहेज़ किया और कहा कि यह तकनीकी मामला निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि उपभोक्ता इस निष्कर्ष से असहमत है, तो वह नियमों के अनुसार उचित मंच पर अपील कर सकता है। आयोग ने यह माना कि उपभोक्ता को एकमुश्त भारी बिल जारी किया जाना अनुचित और उपभोक्ता के प्रति अन्यायपूर्ण है। एसजीआरए द्वारा शिकायतकर्ता को पहले केवल एक हजार रुपये का मुआवजा दिया गया था, जिसे आयोग ने अपर्याप्त माना। अतः, आयोग ने उपभोक्ता को 5 हजार रुपये (अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम सीमा) का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। साथ ही, आयोग ने निर्देश दिया कि यह राशि संबंधित दोषी अधिकारियों से जांच के बाद वसूल की जाए।

श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर नई पीढ़ी राष्ट्र निर्माण में दे योगदान : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा सचिवालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशभर के विद्यालयों में आयोजित निबंध लेखन एवं 'सुनो कहानी श्री गुरु तेग बहादुर जी की' प्रतियोगिता का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के अदम्य साहस, त्याग और सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए कहा कि गुरु साहिब का जीवन सत्य, साहस और मानवता की अनुपम मिसाल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के.एम. पांडुरंग, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री प्रभलीन सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश के विभिन्न स्कूल वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनके विचार सुने और उन्हें श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से सीख लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर चार विद्यार्थियों ने 'साखी वाचन' प्रस्तुत कर श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से जुड़ी प्रेरक घटनाओं को साझा किया। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपने गुरुओं और राष्ट्र नायकों के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक सभी गुरुओं ने हरियाणा की धरती को अपनी चरण धूलि से पवित्र किया है और उनकी शिक्षाएं यहां के जनमानस में गहराई से रची-बसी हैं। मुख्यमंत्री श्री सैनी ने बताया कि इस आयोजन में प्रदेशभर के विद्यालयों से साढ़े तीन लाख से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी हो रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि नई पीढ़ी अपने गुरुओं के आदर्शों और बलिदानों से प्रेरणा ले रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे प्रतियोगिता में पूरे मन से हिस्सा लें और श्री गुरु तेग बहादुर जी के त्याग, सहिष्णुता, समानता और न्याय के संदेश को अपने जीवन में उतारें। उन्होंने कहा कि आज की तकनीकी पीढ़ी को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का उपयोग मानवता, करुणा और भाईचारे का संदेश फैलाने में करना चाहिए। वही श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

***श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री सैनी ने प्रदेशभर में निबंध व कहानी प्रतियोगिता का किया वर्चुअल शुभारंभ**

***हरियाणा के विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद**

उन्होंने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने कर्म और विचारों से राष्ट्र को और मजबूत बनाने का संकल्प लें। यही इस प्रतियोगिता का सच्चा उद्देश्य है।

धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को जल्द मिलेगी रिंग रोड की सुविधा- मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ ।

श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद को देखते हुए कुरुक्षेत्र में रिंग रोड की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसकी डीपीआर लगभग तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि जारी की , जिससे धर्मनगरी को नया स्वरूप मिल रहा है। यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा निवास में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गीता की जन्मभूमि कुरुक्षेत्र को वैश्विक पहचान मिलनी चाहिए और इसी पर कार्य करते हुए प्रदेश सरकार ने कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अनेक कार्यों को अमलीजामा पहनाया है। आज धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में न केवल देश से बल्कि विदेशों से

***कुरुक्षेत्र के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि की जारी**

भारी संख्या में पर्यटक, सैलानी व श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज गीता जयंती महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है। उन्होंने कहा कि धर्मनगरी को भव्य और आकर्षक बनाया जा रहा है। गोतिसर में महाभारत कालीन घटनाओं पर आधारित अनुभव केंद्र बनकर लगभग तैयार है। 25 नवंबर को हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कुरुक्षेत्र आ रहे है, उस दिन वे अंतरराष्ट्रीय गीत महोत्सव में भी शिरकत करेंगे । मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विदेश मंत्रालय विशेष भूमिका निभा रहा है। विदेश मंत्रालय के माध्यम से 24 देशों को निमंत्रण दिए जा चुके है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की परियोजना कृष्ण सर्किट के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र अब सिर्फ तीर्थ नहीं, बल्कि वैश्विक आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस परियोजना के तहत कुरुक्षेत्र के अलावा पिंजौर में पिंजौर गार्डन के जीर्णोद्धार के साथ टिकर ताल का भी सौंदर्यीकरण करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाभारत थीम पर धर्मनगरी सज रही है, मुख्य चौराहों का नामकरण महाभारत के पात्रों के नाम पर किया जा रहा है। पूरे शहर में महाभारत कालीन चित्रकारी करवाई जा रही है। इससे आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक उस युग की रोचक घटनाओं को जीवंत रूप में अनुभव करेंगे। इस अवसर पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर , सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय सहित कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

परिवहन मंत्री अनिल विज ने अम्बाला को दी पांच और नई एसी ई-बसों की सौगात, कुल 15 बसों से अब लोकल सफर बनेगा कूल और ग्रीन

चंडीगढ़ । हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला में पर्यावरण के अनुकूल लोकल/शहरी बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए अम्बाला में पांच और नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) को लोकल रूट पर शामिल किया गया है। 10 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन पहले ही किया जा रहा है। अब पांच नई इलेक्ट्रिक बसें मिलने पर बसों की संख्या कुल 15 हो गई है जोकि पर्यावरण तो स्वच्छ और सफर को आरामदायक बनाऐंगी। उन्होंने बताया कि महानगरों की तर्ज पर अम्बाला में भी लोकल बस सेवा को पूरी तरह से वातानुकूलित ई-बस सेवा में बदलने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के अम्बाला में लोकल बस रूट पर आधुनिक 23 नए बस क्यू शेल्टर बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया जा चुका है। इन बस क्यू शेल्टरों में लोगों के बैठने के साथ-साथ बिजली व लाइट की सुविधा भी होगी। गौरतलब है कि इस समय लोकल परिवहन की बढ़ती मांग को देखते हुए कुल 25 बसों का संचालन परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है जिसमें 15 इलेक्ट्रिक एसी बसें शामिल है। गौरतलब है कि परिवहन मंत्री श्री

बसों के रूट पर 23 आधुनिक बस क्यू शेल्टर का भी हो रहा निर्माण, बैठने की व्यवस्था के साथ पंखे व लाइट की सुविधा भी होगी : अनिल विज

अनिल विज के प्रयासों से अम्बाला में लोकल बस सेवा को लगभग 25 वर्षों बाद पुन प्रारंभ किया जा सका है। श्री विज ने बीते वर्ष 1 नवंबर को 10 मिनी बसों के साथ परिवहन सेवा की शुरूआत की थी। इसके बाद इसी वर्ष गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को लोकल बस सेवा में 5 इलेक्ट्रिक एसी बसों को शामिल किया गया था। अम्बाला में इन रूटों पर चल रही लोकल बस सेवा

यात्रियों के लिए 23 स्थानों पर आधुनिक बस क्यू शेल्टरों का निर्माण शुरू : विज

परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि लोकल बस सेवा का लाभ अधिक से अधिक यात्रियों को बिना किसी दुख तकलीफ के मिले यही हमारी प्राथमिकता है। सर्दी-गर्मी और बरसात के मौसम भी यात्रियों को दिक्कत न हो इसके लिए अम्बाला छावनी में नगर परिषद द्वारा 23 स्थानों पर आधुनिक बस क्यू शेल्टरों का निर्माण किया जा रहा है। आधुनिक क्यू शेल्टर बैठने के अलावा लाइट व पंखे की व्यवस्था से युक्त होंगे।

दिल्ली का नाम बदलने की मांग पर सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया मुद्दों से भटकाने का आरोप

नई दिल्ली।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल की इस मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ हवाई अड्डा करने की बात कही थी. यादव ने इसे जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति बताया है. देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सांसदों के पास दिल्ली की असल समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, इसलिए वे बार-बार नाम बदलने जैसी बातों में जनता को उलझा रहे हैं. उन्होंने कहा, दिल्ली के लोग वायु प्रदूषण, पानी की किल्लत, ट्रैफिक, टूटी सड़कों और महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन भाजपा नेता इन मुद्दों पर चुप हैं. जनता चाहती है समाधान, लेकिन भाजपा दिखावा कर रही है. यादव ने इसे भाजपा का राजनीतिक एजेंडा बताया और कहा कि सरकार विकास की बजाय भावनात्मक मुद्दों के सहारे राजनीति कर रही है. कांग्रेस नेता ने बताया कि इतिहासकारों और विशेषज्ञों ने भी भाजपा सांसद की इस मांग को हास्यास्पद बताया है. उन्होंने कहा, जो सांसद कभी दिल्ली की जहरीली हवा या यमुना की हालत पर आवाज नहीं उठाते, वे अब शहर का नाम बदलने में सक्रिय हैं. सरकारी अस्पतालों में

समाधानों की भारी कमी है, लेकिन भाजपा के किसी नेता ने उस पर एक शब्द तक नहीं बोला. देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीबों से उनकी छतें छीन लीं. उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों पर बुलडोजर चलाया और उन्हें सड़कों पर ला दिया. ये वही लोग हैं जिन्होंने भाजपा पर भरोसा किया था. यादव ने आगे कहा कि दिल्ली पिछले कई सालों से कुशासन झेल रही है. केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में केजरीवाल सरकार दोनों ने मिलकर जनता को ठगा है. उन्होंने कहा बेघर, बेरोजगार और परेशान लोगों की मदद करने की बजाय भाजपा नेता नाम बदलने की राजनीति में उलझे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पिछले आठ महीनों में भाजपा ने कोई ठोस काम नहीं किया. यादव ने कहा चुनाव से पहले महिलाओं को 2500 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक किसी को फायदा नहीं मिला. सबकुछ सिर्फ वादों में सीमित रह गया. उन्होंने यह भी जोड़ा कि दिल्ली सरकार ने शिक्षकों की भर्ती में उम्र सीमा घटाकर हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है. यादव ने आरोप लगाया कि 30 साल की सीमा तय करके भाजपा और आम आदमी पार्टी ने बेरोजगार युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया. देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सांसद जानबूझकर विवाद खड़े कर रहे हैं ताकि जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से हटाया जा सके.

तेलंगाना में सड़क दुर्घटना में 19 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री, राज्य सरकार ने शोक व्यक्त किया

हैदराबाद।

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बजरी से लदे एक ट्रक और एक बस की सोमवार को आमने-सामने की टक्कर होने से 13 महिलाओं एवं एक बच्ची समेत कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

ट्रक हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर चेवेल्ला के पास तेलंगाना सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) की बस से टकरा गया जिसके बाद बजरी बस पर गिर गई। एक जिला अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में 22 लोग

घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने सोमवार को तेलंगाना में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत होने पर शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना में लोगों की मौत होने पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजन को दो-दो लाख रुपये एवं घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। साइबराबाद पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती ने बताया कि दुर्घटना में दोनों वाहनों के चालकों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि आमने-सामने की टक्कर तब होती है जब कोई वाहन गलत दिशा में होता है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का कारण जांच के बाद पता चलेगा। बस पर बजरी गिरने से कई यात्री वाहन के अंदर फंस गए और अधिकारियों ने मशीनों की मदद से बचाव एवं राहत अभियान चलाया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बस में सवार यात्रियों को वाहन से बाहर निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ''तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत होना बेहद दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।'' बयान में कहा गया है, ''प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे।''

जयपुर में डंपर ने 10 गाड़ियों को रौंदा; 13 की लोगों की मौत, 50 घायल

जयपुर। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सोमवार दोपहर एक भयावह सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। लोहा मंडी रोड नंबर 14 पर तेज रफ्तार डंपर ने 300 मीटर तक बेकाबू होकर 10 गाड़ियों को रौंद दिया, जिससे मौके पर 13 लोगों की मौत हो गई और 15 से अधिक घायल हो गए, जिनमें से आठ गंभीर है। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद गाड़ियां परस्पर टकराकर क्षतिग्रस्त हो गईं और सड़क पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस के अनुसार, हादसा दोपहर करीब 1 बजे हुआ, जब डंपर खराब अवस्था में हाईवे पर चढ़ने की कोशिश में था। तभी अचानक उसका ब्रेक फेल हो गया और वह बेकाबू होकर सड़क पर चल रहे वाहनों और राहगीरों को कुचलता चला गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि डंपर लगभग 300 मीटर तक लोगों और गाड़ियों को रौंदता हुआ आगे बढ़ा, जब तक कि वह एक बड़े डिवाइडर से टकराकर रुका नहीं। टक्कर के बाद घटनास्थल पर चारों ओर अफरा-तफरी और दहशत का माहौल फैल गया। घायल लोग सड़क पर तड़प रहे थे और वाहन बुरी तरह मलबे में तब्दील हो गए थे। स्थानीय लोगों ने तत्काल एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद घायलों को पास के कांवटिया अस्पताल भेजा गया, जहां से तीन गंभीर घायलों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। मृतकों के शवों को कांवटिया हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया गया है।

पिता का नाम लेने में क्यों आ रही शर्म, कौन सा पाप छिपा रहे?, पीएम मोदी का तेजस्वी यादव से सवाल

आरजेडी के वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर : पीएम मोदी
पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के किए कामों को गिनाया

कटिहार।

बिहार के कटिहार जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर गुस्सा उतारें और आरजेडी को पराजित करें. पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर सीएम का नाम भी घोषित करा दिया. आरजेडी के पोस्टर से पूर्व सीएम लालू यादव की तस्वीर के गायब होने पर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, आरजेडी कांग्रेस के पोस्टर्स को देखिए, वो (लालू यादव) क्यों यहां के मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगलराज लाए, उनकी तस्वीरें या तो पोस्टर्स में गायब है या छोटी सी लगी है, जो दूरबीन से भी नहीं दिखती. अपने पिता का नाम लेने में शर्म क्यों आ रही है? कौन सा पाप है, जिसे आरजेडी वालों को बिहार के भोजनों से छिपाना पड़ रहा है. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, जो बिहारियों को प्रताड़ित करते हैं, जो बिहारियों को गालियां देते हैं, उनको कांग्रेस ने प्रचार के लिए बुलाया ताकि आरजेडी को आपके गुस्से का सामना करना पड़े. कांग्रेस जानती है कि अगर इस बार भी आरजेडी हार गई तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी और कांग्रेस उसके (आरजेडी) वोट बैंक पर कब्जा कर लेगी. पीएम मोदी ने कहा, अलग-अलग रंगों में कांग्रेस के नेताओं से बिहार के लोगों के लिए जानबूझकर अपमानजनक बातें बुलवाई जा रही है. केरल के कांग्रेस नेता ने बिहार के लोगों की तुलना बीड़ी से कर दी, ये भी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है. बिहार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये लोग वोट पाने के लिए सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं. आपके हक का अनाज ये घुसपैठियों को देना चाहते हैं. भारत के संसाधनों पर सिर्फ यहां के नागरिकों का हक है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के लोगों को कट्टा और कट्टरपंथी ही पसंद है. इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार के किए कामों को भी गिनाया. उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से बिहार की बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच रहे हैं. अभी तक 1.40 करोड़ बहनों के खाते में पैसा आ चुका है. डबल इंजन की एनडीए सरकार का बहुत बड़ा फायदा है. फायदा ये है कि दिल्ली और पटना से निकला एक-एक रुपया सीधे आपके खाते में आता है. कोई चोर-लुटेरा लूट नहीं सकता.

अमित शाह का दावा : मोदी-नीतीश जोड़ी ने बिहार को जंगल राज से दिलाई मुक्ति, खत्म किया वंशवाद

सीतामढ़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी साझेदारी ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई और वंशवाद का अंत किया। उन्होंने राजद के लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार तथा कांग्रेस नेतृत्व पर अपने वंशजों को सत्ता में बिठाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। सीतामढ़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई है। हमने वंशवाद का अंत किया। लालू जी और राबड़ी जी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सोनिया गांधी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। लेकिन मैं लालू-राबड़ी और सोनिया जी को यह बताने आया हूं कि न तो लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और न ही सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी है और नरेंद्र मोदी जी दिल्ली (केंद्र) में सत्ता में हैं। अपने पहले के बयानों को दोहराते हुए गृह मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया मतदाता अधिकार यात्रा पर हमला बोला और इसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताया। शाह ने कहा, राहुल गांधी हाल ही में यहां आए थे। उन्होंने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। रीगा सीमा के पास स्थित है, यह नेपाल के पास है। मुझे बताइए, क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार की मतदाता सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए? ये घुसपैठिए गरीबों के अनाज का हिस्सा हड़प लेते हैं, युवाओं से रोजगार छीन लेते हैं और जो बांग्लादेश से यहां आए हैं, उन्हें यहां वोट देने और बिहार का मुख्यमंत्री चुनने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली बार दावा किया कि पूरा बिहार शाम 5 बजे तक मतदान करेगा क्योंकि अब बिहार नक्सल मुक्त है। उन्होंने कहा, केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी। बिहार के कई जिले नक्सल प्रभावित थे। मतदान दोपहर 3 बजे समाप्त हो जाता था। अब पहली बार पूरा बिहार शाम 5 बजे तक मतदान करेगा क्योंकि अब बिहार नक्सल मुक्त है। 243 सीटों वाली बिहार विधान-सभा के लिए मतदान दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होना है, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर संग्राम, 4 नवंबर को ममता बनर्जी उतरेंगी सड़कों पर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के फैसले को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। गौरतलब है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया का खुलकर विरोध किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी घोषणा की है कि वह अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए मंगलवार (4 नवंबर) को कोलकाता में एक वि शाल विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगी। चुनाव आयोग ने हाल ही में घोषणा की है कि अगले साल होने वाले चुनावों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण चलाया जाएगा। यह एसआईआर 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा और 7 फरवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी।

अधिकारी लोगों की शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें : मुख्यमंत्री शर्मा

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का सोमवार को निर्देश दिया। शर्मा ने यह निर्देश मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जनसुनवाई के दौरान दिया। आधिकारिक बयान के अनुसार, शर्मा ने जनसुनवाई में आई महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं को सबसे पहले सुना और अधिकारियों को उनकी शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। शर्मा ने जनसुनवाई में आए लोगों की कई समस्याओं का संतोषजनक निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, जनसुनवाई में परिवादी अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन से बड़ी उम्मीद रखते हैं। ऐसे में अधिकारी उनकी समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध निस्तारण करें तथा अधिकारी पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ काम करते हुए लोगों को राहत दें।

प्रधानमंत्री को 'अपमान मंत्रालय बना लेना चाहिए ताकि उनका समय व्यर्थ न हो : प्रियंका गांधी

सहरसा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें अलग से एक 'अपमान मंत्रालय बनाना चाहिए ताकि वह बार-बार 'अपमान की सूचियां बनाने में जो समय बर्बाद करते हैं, वो न करें। उन्होंने बिहार के सहरसा जिले के सोनबरसा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं में काम की बात नहीं, बल्कि विपक्षी दलों पर 'अपमान करने के आरोप लगाते हैं। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि बिहार की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, बल्कि केंद्र चला रहा है। उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री हमेशा अतीत की बात करते हैं ये लोग हमेशा कहीं न कहीं से किसी के अपमान की बात निकाल लेते हैं। कर्नाटक में कहा कि विपक्ष ने कर्नाटक का अपमान किया। पश्चिम बंगाल में गए तो पश्चिम बंगाल के अपमान की बात की। बिहार में कह रहे हैं कि विपक्षी दल बिहार का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, ''मेरा सुझाव है कि प्रधानमंत्री एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम 'अपमान मंत्रालय रखें ताकि उनका समय व्यर्थ न हो। वह बड़ी-बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि इसने गाली दी, उसने गाली दी, अपमान किया। वह खुद क्या सूची बनाएंगे, यह 'अपमान मंत्रालय बना देगा। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि बिहार में 65 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काट दिए गए, जिसका मतलब है कि इन लोगों के अधिकार खत्म कर दिए गए। उनका कहना था, ''वोट जनता को कई सारे अधिकार देता है और अगर यही चला जाएगा तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। वोट चोरी जनता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। कांग्रेस नेता ने बिहार सरकार की महिलाओं से संबंधित योजना का हवाला देते हुए कहा, ''नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार चुनाव से हफ्ते भर पहले महिलाओं को 10 हजार रुपये देने की घोषणा करते हैं। ये 10 हजार रुपये, 20 साल से कहां थे? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और जनता दल (यू) की नीयत साफ नहीं है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा, ''इनकी नीयत को पहचानो। इनसे 10 हजार रुपये ले लो, लेकिन इनें अपना वोट मत दो।

योगी आदित्यनाथ ने इंडिया ब्लॉक को बताया पप्पू, टप्पू, अप्पू, कहा- ये सच से दूर!

दरभंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बिहार के दरभंगा में एक जनसभा के दौरान इंडिया ब्लॉक पर तीखा हमला करते हुए कहा, आपने महात्मा गांधी के तीन बंदरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज इंडिया गठबंधन में तीन नए बंदर है, पप्पू, टप्पू और अप्पू। उन्होंने आगे बताया, पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू सही नहीं देख सकता और अप्पू सच नहीं सुन सकता। सीएम योगी ने कहा कि ये नेता एनडीए सरकार के तहत हुए विकास कार्यों को देख, सुन या बोल नहीं सकते, इसलिए ये गलत सूचनाएं फैलाते हैं। राजद-कांग्रेस गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि उनके शासन में गरीबों को बुनियादी जरूरतों और कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा, जब राजद ने कांग्रेस के समर्थन से बिहार पर शासन किया था, तब

गरीबों को राशन और सरकारी योजनाओं से वंचित रखा गया था। 2005 से पहले, कांग्रेस या राजद के शासन में, अगर कोई गरीब बीमार पड़ता था, तो वह तड़प-तड़प कर मर जाता था, क्योंकि कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी। यूपी के मुख्यमंत्री ने कश्मीर को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनकी नीतियों ने ही इसे एक विवादित क्षेत्र बना दिया। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने ही कश्मीर को विवादित बनाया। आज पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में कश्मीर आतंकवाद से मुक्त हो गया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक अभिनेता के बारे में खबर पढ़ी थी जो 27 साल बाद ही कश्मीर जा पाया। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस का पाप था कि हिंदुओं को कश्मीर छोड़ना पड़ा। अब मिथिला और बिहार के लोग भी वहीं शांति से रह सकते हैं। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर सनातन-विरोधी होने और हिंदू आस्था का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कभी भगवान राम और माता जानकी के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। उन्होंने लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर उनके अस्तित्व को नकार दिया। उन्होंने आगे कहा कि राजद ने राम रथ यात्रा रोकने की कोशिश की और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलीबारी का आदेश देकर पवित्र नगरी को खून से लाल कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी परिवार माफिया का समर्थन करके और घुसपैठियों को आमंत्रित करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रही है।

पीएम की गोद में बैठे हैं नीतीश, लेकिन मोदी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे : खरगे

वैशाली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ''कुर्सी के लालच में'' समाजवाद, कर्पूरी ठाकुर तथा राममनोहर लोहिया को भूलने का आरोप लगाया और दावा किया कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ''गोद में बैठे हैं'', लेकिन मोदी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले हैं। उन्होंने बिहार के वैशाली जिले के राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि नीतीश के दिल में दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए जगह होती तो वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ कभी नहीं जाते। खरगे ने कहा, ''अब ये

(नीतीश) मोदी की गोद में बैठे हैं। यह लिखकर रख लो वह (प्रधानमंत्री) नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। वह अपने किसी चेले को बना देंगे और कहेंगे कि नीतीश जी, आपकी तबियत ठीक नहीं है, आप घर बैठकर आराम करिए, हम आपकी औषधि का इंतजाम करते हैं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार कुर्सी के लालच में समाजवाद, कर्पूरी ठाकुर और लोहिया को भूल गए। खरगे ने कहा, ''नीतीश कुमार कुर्सी को पकड़कर बैठे हैं, वह नहीं छोड़ना नहीं चाहते।'' उन्होंने दावा किया कि यदि नीतीश के दिल में पिछड़े, दलित और अति पिछड़े के लिए जगह होती तो वह उस भाजपा के साथ कभी नहीं जाते जो मनुस्मृति में विश्वास करती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार में कई सभाएं करने पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री ऐसे घूम रहे हैं कि मानो उनके बेटे की शादी हो।'' उन्होंने कहा कि निकाय, तालुका और विधानसभा, सभी चुनाव में प्रधानमंत्री घूमते रहे हैं। खरगे ने कहा कि केंद्र के स्तर पर 50 लाख सरकारी पद खाली हैं, लेकिन बिहार में एक करोड़ नौकरी देने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में बिहार से लोगों का बड़ी संख्या में पलायन हुआ है।

राजनीतिक पार्टियों के नियमों को लेकर जनहित याचिका दायर, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग-केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दरअसल जनहित याचिका में मांग की गई है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दिए जाएं कि वे अपने उद्देश्यों, नियम कायदों की जानकारी आधिकारिक पेज पर प्रकाशित करें। याचिका में मांग की गई है कि राजनीतिक पार्टियों की जवाबदेही और पारदर्शिता तय की जाए। यह याचिका वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की

थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने राजनीतिक पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए एक जनहित याचिका दायर की है। जब तक संसद इस पर कोई कानून नहीं बनाती, तब तक सुप्रीम कोर्ट को दिशा-निर्देश बनाने चाहिए। अदालत ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों से जवाब मांगा है, क्योंकि अभी इस मामले से निपटने के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग, कानून मंत्रालय और कानून आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग , जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29बी और 29सी को लागू कराने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे। याचिका में कहा गया है कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक पार्टियों के ईर्द-गिर्द रहती है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां लगातार जनता की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से जुड़ी होती है, ऐसे में जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियों की जवाबदेही तय हो।